



Neutral Citation No. - 2026:AHC:36543

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1403 वर्ष 2025

विकास चौहान

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: जुनैद आलम

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, प्रदीप कुमार

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की बात सुनी गई और रिकॉर्ड पर प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन किया गया।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि दिनांक 6.4.2025 की एफ.आई.आर. बी.एन.एस. की धारा 87, 137(2), 64 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5एम/6, 11(4)/12 के तहत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 5.4.2025 को आवेदक ने शिकायतकर्ता की लगभग 18 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया था। पीड़िता के बरामद होने पर, बी.एन.एस.एस. की

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



धारा 180 और 183 के तहत उसके बयान दर्ज किए गए, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा कि घटना की तारीख को वह आवेदक के साथ अपनी मर्जी से गई थी और उनका विवाह संपन्न हुआ और वे पति-पत्नी के रूप में साथ रहने लगे और अब वह गर्भवती है और अभी भी आवेदक के घर पर रह रही है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि पीड़िता के बयानों के अनुसार, वह सहमति देने वाली पक्षकार प्रतीत होती है और आवेदक को झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की असत्यता सिद्ध करने के लिए कई अन्य निवेदन भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया है, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि वह विधि के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि आवेदक 04.09.2025 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

3. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का यह तर्क देते हुए विरोध किया है कि आवेदक की निर्दोषता का निर्णय मुकदमे से पहले के चरण में नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है।

4. सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता है। तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. आवेदक **विकास चौहान** को वाद अपराध संख्या 133/2025 में, बीएनएस की धारा 87, 137(2), 64 और बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम की धारा 5M/6, 11(4)/12 के तहत, पुलिस स्टेशन-तमकुहिराज, जिला- कुशीनगर में, व्यक्तिगत मुचलके पर जमानत पर रिहा किया जाए। बहिष्कार करने और दो स्थानीय जमानतदारों को समान राशि में प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के साथ:

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
 - iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
 - iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा, जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का संदेह है।
 - v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, ताकि उस व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
6. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

18 फरवरी, 2026

जीएसएस

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"